



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1966]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2018/ज्येष्ठ 9, 1940

No. 1966]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2018/JYAISTHA 9, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2018

**का. आ. 2180(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2147 (अ) के तहत आईजोल के जिला तथा सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मिजोरम राज्य था;

और जबकि, श्रीमती लुसी लालरिन्थारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आईजोल जिनको भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 2839 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2839 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया हो अथवा करने से लोप किया गया हो, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद्वारा श्री जोएल जोसफ डेंगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आईजोल को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस- IV (पार्ट- I) (खण्ड-II)]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2018

**S.O. 2180(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2147 (E) dated the 1<sup>st</sup> September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of District and Sessions Judge, Aizawl, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Mizoram for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Smt. Lucy Lalrinthari, District and Sessions Judge, Aizawl, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2839 (E) dated the 15<sup>th</sup> October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 2839 (E), dated the 15<sup>th</sup> October, 2015, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, The Gauhati High Court at Guwahati, hereby appoints Shri Joel Joseph Denga, District and Sessions Judge, Aizawl, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-I) (Vol. II)]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.